इकाई 21

नागरिक समाज और लोकतंत्र

इकाई की रूपरेखा

21.1 प्रस्तावना

21.2 नागरिक समाजः एक पुनरावलोकन

21.3 लोकतंत्रः एक सार्वभौमिक मांग

21.4 नागरिक समाज का क्षेत्र

21.5 नागरिक समाज और लोकतंत्र में संबंध

21.6 लोकतांत्रिक व्यवस्था में नागरिक समाज के कार्य

21.7 लोकतंत्र के प्रवर्तक के रूप में नागरिक समाज

21.8 नागरिक समाज के लोकतांत्रिक खतरे

21.9 सारांश

21.10 कुछ उपयोगी पुस्तकें

अधिगम उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के बाद, आपः

- 'नागरिक समाज क्या है' को स्पष्ट कर सकेंगे;
- नागरिक समाज और लोकतंत्र के बीच संबंध को रेखांकित कर सकेंगे; और
- नागरिक समाज के खतरों का लोकतंत्रीकरण कर सकेंगे।

21.1 प्रस्तावना

पिछले कुछ वर्षों में नागरिक समाज की अवधारणा और लोकतंत्र के प्रति चिंता ने शैक्षणिक चर्चाओं, बहस और लेखन में पूरे विश्व में एक महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है। विचार की दुनिया में नागरिक समाज का मुद्दा गर्म है। इस अवधारणा की चर्चा के बिना गृह अथवा विदेश नीति पर कोई एक लेख भी मिल पाना असम्भव है। यद्यपि नागरिक समाज और लोकतंत्र की शब्दावली उतनी ही पुरानी है जितना समाजशास्त्र की, परंतु फिर भी इसके अर्थ और सार में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है। इन अवधारणाओं को समझने के लिए इन अवधारणाओं के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य पर एक नजर डालना अच्छा रहेगा जहां भिन्न-भिन्न बुद्धिजीवियों ने इस दिशा में अपने विचार रखे हैं।

21.2 नागरिक समाजः एक पुनरावलोकन

नागरिक समाज की लोकप्रियता का मुख्य कारण लैटिन अमरीका, अफ्रीका और पूर्व साम्यवादी विश्व के प्रतिरोधी समूहों द्वारा अत्याचार के विरुद्ध किया गया संघर्ष है। 1980 और 1990 के काल ने विश्व स्तर पर अप्रत्याशित लोकतांत्रिक क्रांति का दौर देखा जब विभिन्न संघों, महिला संस्थाओं, छात्र समूहों और अन्य प्रकार की लोकप्रिय सक्रियता ने विद्रोही और पुनर्जीवित समाजों को कई प्रकार की तानाशाही समाप्त करने का बल प्रदान किया। इन घटनाओं ने इस जटिल विचार को प्रोत्साहित किया कि यदि एक पुनर्जीवित

नागरिक समाज लोकतांत्रिक परिवर्तन ला सकता है.तो वह इसे पुष्ट भी कर सकता है।

'नागरिक समाज' शब्द को सिसरो तथा अन्य रोमन से लेकर यूनानी दार्शनिकों के लेखन में ढूँढा जा सकता है। अपने शास्त्रीय प्रयोग में इस शब्द को राज्य के समान अर्थ में प्रयुक्त किया जाता था। नागरिक समाज के आधुनिक विचार को 18वीं सदी के अंतिम वर्षों में स्काटिश और महाद्वीपीय जागरण में अभिव्यक्ति मिली। यहाँ राजनैतिक दार्शनिकों की एक लम्बी श्रृंखला, थॉमस पेयन से लेकर जॉर्ज हीगल तक ने नागरिक समाज के विचार को राज्य के समान्तर परंतु राज्य से भिन्न विकसित किया, जिसमें नागरिक अपनी इच्छा और हितों के अनुसार जुड़ते हैं। नागरिक समाज की अलाभकारी समकालीन अवधारणाओं के विपरीत हीगल के उन्नीसवीं सदी के नागरिक समाज में बाजार सम्मिलित था। इस नई परिभाषा ने बदलती आर्थिक सच्चाइयों — निजी सम्पत्ति में वृद्धि, बाजारी प्रतिस्पर्धा और बुर्जुआवाद को उजागर किया। इसका परिणाम अमरीकी, इंग्लिश और फ्रांसीसी क्रांतियों में व्यक्त स्वतंत्रता की बढ़ती माँग के रूप में हुआ।

इस शब्द ने 19वीं सदी के मध्य में अपनी सार्थकता खो दी क्योंकि तब राजनीतिक दार्शनिकों और समाज विज्ञानियों का ध्यान औद्योगिक क्रांति के सामाजिक और राजनीतिक परिणामों की ओर मुड़ गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पुनः यह शब्द लौटकर आया जब मार्क्सवादी विचारक एन्टोनियो ग्रेम्सी ने नागरिक समाज को स्वतंत्र राजनीतिक गतिविधियों के केंद्र, अत्याचार के विरुद्ध महत्वपूर्ण संघर्ष के क्षेत्र के रूप में दर्शाने के लिए प्रयुक्त किया। यद्यपि ग्रेम्सी के लिए दक्षिणपंथियों की तानाशाही चिन्ता का विषय थी परंतु उसकी पुस्तकें 1970 और 1980 के दशक में पूर्वी यूरोप और लातीनी अमरीका में सभी राजनीतिक रंगों की तानाशाही के विरुद्ध लड़ने वाले लागा में लोकप्रिय थीं। चेक, हंगरी और पोलैण्ड के क्रांतिकारियों ने अपने आप को नागरिक समाज के झंडे के नीचे एकत्र कर लिया और बर्लिन की दीवार गिरने पर इसे वीरता के गुण से सम्मानित किया।

इस अवधारणा का महत्व देखते हुए डेविड हैल्ड ने नागरिक समाज की अवधारणा को सामाजिक परिभाषा के माध्यम से एक रूप देने का प्रयास किया। उसके शब्दों में, 'नागरिक समाज का अपना इस हद तक एक विलग चरित्र है कि यह सामाजिक जीवन और घरेलू दुनिया के क्षेत्रों से निर्मित है जिसमें राज्य के सीधे नियंत्रण से बाहर व्यक्तियों और समूहों की बीच निजी और स्वैच्छिक प्रबंध में व्यवस्थित आर्थिक क्षेत्र, सांस्कृतिक गतिविधियां और राजनीतिक व्यवहार एवं अंतर्संबंध सम्मिलित हैं।

1990 के दशक में यकायक नागरिक समाज राष्ट्राध्यक्षों से लेकर राजनीतिक विज्ञानियों तक, सबके लिए एक मंत्र बन गया। लोकतंत्र के प्रति वैश्विक झुकाव ने पूरी दुनिया के पूर्व तानाशाही देशों में नागरिक समाज के लिए स्थान बनाया। संयुक्त राज्य और पश्चिमी यूरोप में थकी हारी दलीय व्यवस्था में ग्रस्त और त्रस्त लोगों में सामाजिक नवीनीकरण के माध्यम के रूप में नागरिक समाज में रुचि को जागृत किया। विशेषतः विकासशील देशों में निजीकरण एवं अन्य बाजार सुधारों ने नागरिक समाज को वहां कदम रखने का अवसर प्रदान किया जहां से सरकार पीछे हट चुकी थीं। और सूचना क्रांति ने नागरिकों के सशक्तिकरण तथा संबंधों के निर्माण के लिए नए साधन प्रदान किए। शीत युद्ध के बाद की स्थिति में नागरिक समाज एक महत्वपूर्ण तत्व बन गया है।

21.3 लोकतंत्रः एक सार्वभौमिक मांग

नागरिक समाज की भांति लोकतंत्र भी अलग-अलग स्थानों और समय पर एक तरल अवधारणा रही है। पुरातन एथेन्स के लोकतंत्र और आधुनिक उदार लोकतंत्र, प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र तथा वाद-विवादयुक्त लोकतंत्र, राष्ट्रीय लोकतंत्र तथा सर्वदेशीय लोकतंत्र में तीव्र विरोधाभास देखा जा सकता है।

इसके बावजूद भी लोकतंत्र की इन सभी अवधारणाओं में यह संयुक्त उद्देश्य निहित है कि लोकतंत्र ऐसी परिस्थिति है जहां एक समाज संयुक्त रूप से आत्म निर्णय करता है। लोकतंत्र के माध्यम से एक जन समूह के सदस्य संयुक्त निर्णय लेते हैं जो उनके भाग्य को बनाता है, जिसमें वाद-विवाद पर बिना किसी रोक के समान अधिकार और भागीदारी के अवसर मिलते हैं। स्थान की कमी को देखते हुए यह कहना पर्याप्त रहेगा कि लोकतंत्र अवश्य ही सहभागिता, विचार-विमर्श, पारदर्शिता और जनता के प्रति जवाबदेही से युक्त है। एक तरीके से या दूसरे तरीके से लोकतांत्रिक शासन, शासित की सहमति पर निर्भर करता है। बल देते हुए कहा जा सकता है कि लोकतंत्र का निर्माण संदर्भ के आधार पर होता है और यदि संदर्भ बदल जाए तो इसका पुनर्निर्माण करना चाहिए। समकालीन भूमंडलीकरण (वैश्वीकरण) इस प्रकार से स्थिति परिवर्तन कर रहा है कि जिसमें लोकतंत्र के प्रति नई प्रवृत्तियों की आवश्यकता है।

स्मिटर और कार्ल के अनुसार स्पष्टता और निरंतरता के लिए आधुनिक राजनीतिक लोकतंत्र को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है - "शासन की एक ऐसी प्रणाली जिसमें शासक जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के सहयोग से किए गए कार्यों के लिए अप्रत्यक्ष रूप से जनता की अदालत में जवाबदेह होता है।"

इससे पहले कि हम नागरिक समाज और लोकतंत्र के बीच संबंधों का परीक्षण करें कि वे कहां तक एक दूसरे को बढ़ाने में एक दूसरे के पूरक हैं, हमें नागरिक समाज की गुमराह करने वाली अवधारणा पर विचार कर लेना चाहिए।

21.4 नागरिक समाज का क्षेत्र

नागरिक समाज के प्रति वर्तमान उत्साह का अधिकांश भाग इसके गैर-सरकारी संस्थाओं के प्रति, विशेष रूप से जनहित से जुड़े समर्थक समूह तथा पर्यावरण, मानवाधिकार, महिलाओं की समस्याओं, विकलांगों के अधिकार, चुनाव पर निगरानी, भ्रष्टाचार विरोधी संस्थाओं के प्रति आकर्षण के कारण है। ऐसे समूहों की गिनती में पिछले वर्षों में वृद्धि हुई है और विशेष रूप से उन देशों में जो अभी लोकतांत्रिक परिवर्तन के दौर से गुजर रहे हैं। यद्यपि नागरिक समाज की मात्र गैर-सरकारी संस्थाओं से बराबरी करना गलत होगा। नागरिक समाज की अवधारणा काफी विस्तृत है जिसमें राज्य के बाहर की सभी संगठन और संस्थाएं जिनमें राजनीतिक दल तथा बाजारोन्मुख संगठन सम्मिलित हैं तथा इसमें वे सभी संस्थाएं भी शामिल हैं जिन्हें राजनीतिक विज्ञानी हित समूह तथा दबाव समूह कहते हैं। गैर-सरकारी संस्थाओं से अतिरिक्त मजदूर संघ, व्यवसायिक संस्थाएं (डॉक्टर तथा वकीलों की) चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, जातीय संस्थाएं इत्यादि शामिल होती हैं। यह सूची बहुत विस्तृत है । इसमें कई अन्य संस्थाएं जो कुछ विशिष्ट सामाजिक और राजनीतिक कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के उद्देश्य के अतिरिक्त अन्य काम कर रही हैं जैसे धार्मिक संगठन, छात्र समूह, सांस्कृतिक संस्थाएं, खेल क्लब और अनौपचारिक समुदायिक समूह इत्यादि भी सम्मिलित हैं।

गैर-सरकारी संस्थाएं विकसित एवं विकासशील देशों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। वे नीति निर्माण में सरकारों पर दबाव डालकर तथा नीति निर्माताओं को तकनीकी सहायता प्रदान कर नीति निर्माण में सहायता करती हैं। वे राजनीतिक सहभागिता एवं नागरिक शिक्षा को प्रवृत्त करती हैं। वे ऐसे नवयुवकों को नेतृत्व का प्रशिक्षण देती हैं जो समाज में कुछ करना चाहते हैं पर जिन्हें राजनीति में कोई रुचि नहीं होती।

धर्म आधारित एवं तानाशाही देशों में परम्परागत नागरिक समाज गैर-सरकारी संस्थाओं को अधिक महत्व देता है। धार्मिक, सांस्कृतिक संस्थाएं एवं अन्य समूहों का प्रायः जनता में विस्तृत आधार होता है और वे अपने लिए आवश्यक निधि के घरेलू साधन प्राप्त कर लेते हैं। यहां वकालत करने वाले समूहों को प्रायः घरेलू धन की कमी रहती है।

ऐसे देशों में नई-नई गैर-सरकारी संस्थाओं में प्रायः विशिष्ट वर्ग का प्रभुत्व होता है और उनका जन साधारण के साथ क़मजोर सा रिश्ता होता है और वे अपनी गतिविधियों के लिए अधिकतर अंतरराष्ट्रीय निधि देने वालों पर निर्भर रहते हैं। और वे अपना खर्च घरेलू साधनों से पूरा नहीं कर सकते।

यहाँ यह संकेत देना ठीक होगा कि नागरिक समाज निर्माण की इस सकारात्मक रूपरेखा के अतिरिक्त माफिया और लड़ाकू समूह भी नागरिक समाज के उतने ही अंग हैं जितनी अन्य मानवीय संस्थाएं हैं। कुछ उत्साही नागरिक समाज के समर्थकों ने केवल एक तरफा रवैये को ही प्रचारित किया है कि नागरिक समाज में केवल श्रेष्ठ उद्देश्य और लोक कल्याण के कार्यक्रम सम्मिलित होते हैं। लेकिन फिर भी समाज अच्छे, बुरे और जंगली लोगों का मिश्रण है। इन्टरनेट पर वेब पेजिज़ की सर्फिंग से यह भाव स्पष्ट होता है कि नागरिक समाज के वास्तविक क्षेत्र में विभिन्नता होती है। यदि नागरिक समाज को उच्च मानवीय उद्देश्यों को मानने वालों तक सीमित कर दिया जाए तो यह अवधारणा केवल अध्यात्मवादी धारणा बन जाएगी न कि राजनीतिक अथवा सामाजिक, जो समाज के विचार पर ही प्रहार होगा।

21.5 नागरिक समाज और लोकतंत्र में संबंध

यहाँ इस बात पर बल दिया गया है कि कुछ परिस्थितियों में नागरिक समाज सत्तावादी शासन को लोकतांत्रिक बनाने में सहायक हो सकता है और एक बार लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था स्थापित हो जाए तो उसे जीवित रखने में भी सहायक हो सकता है। उदाहरण के लिए, पूर्वी यूरोपीय देशों, दक्षिण अफ्रीका, सर्बिया, फिलिपीन और पिछले दिनों जार्जिया में नागरिकों ने नागरिक समाज की संस्थाओं का प्रयोग राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए लाखों साथी नागरिकों को दमनकारी शासनों के विरुद्ध लामबंद कर संघर्ष किया। लोकतांत्रिक व्यवस्था में नागरिक समाज की संस्थाएं नागरिकों को राजनीतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक क्षेत्र में संयुक्त हितों को प्राप्त करने के लिए आधार प्रदान करती हैं, यहाँ लोग स्वतंत्र, सामूहिक और शांतिपूर्ण ढंग से भागीदारी करते हैं। सामाजिक संस्थाओं में शामिल होने से नागरिकों को सहभागिता और संयुक्त कार्यवाही के मूल लोकतांत्रिक मूल्यों की शिक्षा मिलती है जिन्हें वे आगे जाकर अपने समुदाय के लोगों के बीच प्रसारित करते हैं। नागरिकों के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले नागरिक समाज के आन्दोलन, सरकारी नीति और सामाजिक प्रवृत्ति को काफी हद तक प्रभावित कर सकते हैं। नागरिक समाज की स्वतंत्र गतिविधियां, राज्य शक्ति के बराबर खड़ी हो सकती हैं।

बॉक्स 21.1: जनता की शक्ति

कई पश्चिमी दिमागों में नागरिक समाज का विचार तानाशाहों को खदेड़ बाहर निकालने के जन शक्ति आंदोलनों से जुड़ा हुआ है। सफल पश्चिमी लोकतंत्र द्वारा दुनिया के भिन्न-भिन्न भागों में नागरिक समाज को मजबूत करने का कार्यक्रम अमरीका और पूर्वी देशों का मानक कार्यक्रम बन गया है। इसे लोकतंत्र वृद्धि के यंत्रों की किट भी कहते हैं । थॉमस कैरोथर्स और मैरीना औटावे ने लोकतंत्र को मजबूत करने में अंतरराष्ट्रीय समुदाय और नागरिक समाज की सक्रिय सामूहिक भूमिका की चर्चा में दो रोचक योगदान दिए हैं। 'एडिंग डेमोक्रेसी अब्राड' अमरीकी लोकंत्र के विस्तार की वर्तमान क्रियाकलापों पर एक वृहद और महत्वपूर्ण प्रकाशित पुस्तक है। कैरोथर्स अंतरराष्ट्रीय संबंधों में जाए बिना 'लोकतंत्र विस्तार को एक रणनीति' के रूप में चर्चा करता है जो यथार्थवादी सुरक्षा हितों अथवा आदर्शवादी, मानवीय प्रेरणा के अनुरूप है। वह यह दावा करता है कि लोकतंत्र दोनों का मिश्रण है।

अपने दृष्टिकोण को ठीक ढंग से प्रस्तुत करने के लिए उसने लोकतंत्र के लिए सहायता (डेमोक्रेसी एड) के तीन केंद्रीय पक्षों का वर्णन किया — चुनावी सहायता, संस्थात्मक सुधार और नागरिक समाज सहायता। वह इसे स्पष्ट करने के लिए अमरीका से विभिन्न प्रकार की सहायता प्राप्त करने वाले देशों — गुएटमाला, नेपाल, जाम्बिया और रोमानिया के मामलों के अध्ययन का विस्तृत वर्णन करता है।

कैरोथर्स के विचार में लोकतंत्र सहायता (डेमोक्रेसी एड) लोकतंत्रीकरण की उपज है न कि इसके उलट। लोकतांत्रिक होते राज्यों से बने वातावरण और परिस्थितियों ने इन देशों में लोकतंत्र को बढ़ाने में अंतरराष्ट्रीय सहायता के योगदान को सम्भव बनाया है। निष्कर्ष निकालते हुए वह यह टिप्पणी करता है कि स्थानीय संदर्भों में अंतर होने के बावजूद लोकतंत्र को बढ़ाने के लिए अमरीका की गतिविधियां सब के लिए एक ही नीति का प्रयोग करती हैं, जो कोई स्वस्थ तरीका नही है। लोकतंत्र की सहायता का यह तरीका शैक्षणिक सिद्धांतों के सतर्क प्रयोग से नहीं अपितु व्यवहार के दौरान विकसित हुआ है।

विश्व के अलग-अलग भागों में नागरिक समाज को मजबूत करने की प्रक्रिया को वाशिंगटन में व्याप्त इस प्रश्न के उत्तर के रूप में प्रस्तुत किया जाता है कि किस प्रकार अरब के देशों को लोकतांत्रिक किया जा सकता है और अमरीका को वहां लोकतंत्र की सहायता के लिए क्या करना चाहिए।

यद्यपि अन्य देशों के आंतरिक मामलों में अमरीका के दखल देने का समर्थन नहीं किया जा सकता तथापि विद्वानों में यह सहमति है कि लोकतंत्र को स्थापित करने में नागरिक समाज का सबसे पहला स्थान है। जॉन केन अपने इस कथन के माध्यम से अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है — "जहाँ कोई नागरिक समाज नहीं है वहाँ एक राजनीतिक कानूनी ढाँचे के अंतर्गत अपनी विशिष्टता, अधिकार और कर्त्तव्यों को चुनने योग्य नागरिक नहीं हो सकते"।

21.6 लोकतांत्रिक व्यवस्था में नागरिक समाज के कार्य

लोकतांत्रिक राजनीति को आगे बढ़ाने में नागरिक समाज के कार्यों पर प्रकाश डालते हुए लारी डायमंड अपने लेख "रिथिंकिंग सिविल सोसायटी (1996)" में कहता है "नागरिक समाज लोकतंत्र का स्थापित करने और मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है"। उसका विचार है कि लोकतांत्रिक नागरिक समाज में यह संभावनाएं अधिक हैं कि लोकतंत्र का उदय होगा और वह स्थायी होगा।" डायमंड के विचारानुसार नागरिक समाज अधोलिखित महत्वपूर्ण कार्य करता है:

1) राज्य के राजनीतिक दुर्व्यवहार और कानूनी उल्लंघन को रोक कर तथा जनता द्वारा इसकी छानबीन कर राज्य शक्ति को सीमित करना। डायमंड का यह दृढ़ मत है कि नागरिक समाज लोकतंत्र की शुरुआत करने से अधिक लोकतंत्र को बनाए रखने व मजबूत करने के लिए आवश्यक है।

2) लोकतंत्र नागरिकता के अधिकारों और कर्त्तव्यों के प्रति उत्साह में वृद्धि करके तथा लोकतांत्रिक नागरिकों की राजनीतिक कुशलता एवं कौशल में वृद्धि के माध्यम से नागरिकों को सशक्त करना।

3) नागरिकों में लोकतांत्रिक गुणों, जैसे — सहनशीलता, विनम्रता, समझौते करने की इच्छा तथा विरोधी विचारों का सम्मान करना — को पैदा करना एवं विस्तार देना। डायमंड के अनुसार यह एक महत्वपूर्ण कार्य है क्योंकि यह परम्परागत रूप से विलग किए गए समूहों जैसे महिलाओं, जातीय और वंशानुगत अल्पसंख्यकों को सत्ता तक पहुंचने का अवसर प्रदान करता है जिनसे उन्हें औपचारिक राजनीति के उच्च गलियारों द्वारा वंचित रखा गया है।

4) राजनीतिक दलों एवं अन्य संस्थाओं को अपने हितों को प्रस्तुत करने के लिए मुखर एवं एकत्र होने के अवसर प्रदान करना। इससे लोकतंत्र की गुणवत्ता में वृद्धि होती है क्योंकि यह प्रशासन के हर स्तर पर प्रतिभागिता और प्रभावित करने के अवसर पैदा करता है और स्थानीय शासन में भी ऐसे अवसर उत्पन्न होते हैं।

5) भर्ती करने, सूचना और नेतृत्व पैदा करने वाली एजेंसी के रूप में कार्य करना — विशेषतः आर्थिक रूप से विकसित उन देशों में जहाँ कभी-कभी आर्थिक सुधार आवश्यक तो होते हैं परंतु कर पाना कठिन होता है क्योंकि इससे निहित आर्थिक स्वार्थों को खतरा होने लगता है। इंडोनेशिया में आर्थिक व्यवस्था के ढह जाने से बड़े पैमाने पर असंतोष फैल गया जिससे अचानक ही राष्ट्रपति सुहार्तो संदेह के घेरे में आ गए। इससे वातावरण में बदलाव आया जिसने नागरिक समाजों और विपक्षी दलों को अप्रत्याशित ढंग से लामबंद होने की छूट दी।

6) एक सुदृढ़ आधार वाला नागरिक समाज झटके सहन करने में सक्षम होता है जहाँ हितों की एक लम्बी श्रृंखला एक दूसरे को लांघ कर राजनीतिक विवाद को शांत करती हों।

7) सफल आर्थिक एवं राजनीतिक सुधारों को प्रारम्भ करना, जिसके लिए समाज और विधायिका में गठबंधनों के सहयोग की जरूरत होती है।

8) एक मजबूत आधार वाला नागरिक समाज नए राजनीतिक नेतृत्व की पहचान एवं उसे प्रशिक्षित करता है । इस प्रकार से यह सीमित और पुराने ढंग से दलीय प्रभुता वाले नेताओं को भर्ती करने के तौर-तरीकों में नई ऊर्जा भरने में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

9) चुनावों की निगरानीः अनेकं गैर-राजनीतिक संस्थाएं देश-विदेश में चुनाव निगरानी का काम करती हैं। डायमंड कहते हैं कि इस प्रकार के प्रयास धोखाधड़ी को पकड़ने, मतदाताओं का विश्वास बढ़ाने, चुनावी परिणामों की वैधता को स्वीकार करने तथा सरकार की धोखाधड़ी के बावजूद विपक्ष की जीत दर्ज कराने में — फिलीपाईन्स और 1989 में पानामा को उदाहरण के रूप में लिया जा सकता है।

   क) नागरिकों की राज्य की ओर प्रवृत्ति को मजबूती प्रदान करने से राजनीतिक व्यवस्था की जवाबदेही, जिम्मेवारी, सम्भागिता, प्रभावशीलता और वैधता बढ़ जाती है। इस प्रकार से यह नागरिकों के मन में राज्य के प्रति आदर और इसमें सकारात्मक प्रतिभागिता पैदा करती है। यहाँ नागरिक समाज स्थायी, गुणवत्तापूर्ण और संवेदनशील लोकतंत्र के विकास और अस्तित्व के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

10) इसके साथ ही अन्य विचारकों ने भी इस विषय पर अपने दृष्टिकोण प्रस्तुत किए हैं। लोकतंत्र पर रॉबर्ट डहल के शास्त्रीय कार्य से प्रेरणा लेते हुए अल्फर्ड स्टेपन ने अपनी कृति 'प्रोब्लम ऑफ डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन एंड कंसोलिडेशन — लोकतंत्र के संक्रमण एवं पुष्टिकरण की समस्याए — में लिखा है कि लोकतंत्र के लिए आधारभूत आवश्यकताओं में प्राथमिकताएं निर्मित करना, प्राथमिकताओं का अर्थ निश्चित करना तथा सरकार के संचालन में इन प्राथमिकताओं के महत्व की जाँच करना शामिल है। राबर्ट डहल के अनुसार सरकार के सुचारु रूप से कामकाज करने के लिए इसे निम्नलिखित सांस्थानिक गारंटी सुनिश्चित करनी चाहिएः

   1) सभा एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता।

   2) मतदान का अधिकार।

3) सरकारी पदों के लिए मुकाबला।

4) निष्पक्ष एवं स्वतंत्र चुनाव।

5) समर्थन एवं मतों के लिए मुकाबले का राजनीतिक अधिकार।

6) सूचना के वैकल्पिक स्रोत।

7) नीति निर्माण की संस्थाओं का मतों पर निर्भर होना।

8) प्राथमिकताओं की अन्य अभिव्यक्तियाँ।

बॉक्स 21.2: आधारभूत स्वतंत्रताएं

यद्यपि स्टेपन सांस्थानिक प्रतिश्रुतियों (guarantees) के महत्व को स्वीकार करते हुए इन्हें आवश्यक समझता है परंतु लोकतंत्र के कामकाज के लिए पर्याप्त नहीं मानता। उसके विचारानुसार कितने ही स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव क्यों न हो, चाहे सरकार के पास कितना ही बहुमत हो परंतु एक राजनीतिक समाज में गुणवत्ता का अभाव रहेगा यदि वह एक ऐसा संविधान निर्मित करने में अक्षम है जिसमें आधारभूत स्वतंत्रताएं हों, अल्पसंख्यकों के अधिकार तथा कुछ संस्थाएं तथा राज्य शक्ति को सीमित करने वाले नियंत्रण और संतुलन तथा किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था की जवाबदेही सुनिश्चित करना शामिल न हो।

21.7 लोकतंत्र के प्रवर्तक के रूप में नागरिक समाज

अपने लेख "वैश्विक शासन में नागरिक समाज और लोकतंत्र" में डॉ. जेन आर्ट शाल्ट ने इन अवधारणाओं का गहन विश्लेषण किया है। वह नागरिक समाज और लोकतंत्र के केवल सकारात्मक पहलुओं की ही कल्पना नहीं करती अपितु इसके नकारात्मक पहलुओं का भी मूल्यांकन करती है। लोकतांत्रिक सरकार के प्रवर्तक के रूप में नागरिक समाज का सकारात्मक पक्ष लेते हुए शाल्ट (Scholte) ने ऐसे छह क्षेत्रों की पहचान की है जहाँ नागरिक समाज लोकतंत्र को बढ़ावा दे सकता है।

1) **जन-शिक्षाः** जागरूकता लोकतांत्रिक व्यवस्था का मूल मंत्र है। जनता को शिक्षित करने के माध्यम से नागरिक समाज लोकतंत्र को बढ़ावा दे सकता है। ज्ञानवान नागरिक प्रभावी लोकतंत्र को जीवित रख सकते हैं, नागरिक संस्थाएं दुनिया भर में प्रचलित कानूनों और नियामक संस्थाओं के प्रति जागरूकता पैदा करने के माध्यम से अत्यधिक योगदान कर सकती हैं। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए नागरिक समाज छोटी पुस्तिकाएं एवं सूचना थैलियां तैयार कर सकता है, दृश्य-श्रव्य सामग्री बना सकता है, कार्यशालाएं चला सकते हैं, समाचार पत्र प्रसारित कर सकते हैं, जनसंचार के माध्यमों को सूचनाएं दे सकते हैं और उनका ध्यान आकर्षित कर सकते हैं, इंटरनेट पर वेब साईट बना सकते हैं, उच्च शिक्षा के संस्थानों एवं स्कूलों के लिए प्रचार सामग्री बनाई जा सकती है।

2) **दावेदारों की आवाज बनानाः** नागरिक समाज दावेदारों को समर्थन देकर लोकतांत्रिक शासन को बढ़ावा दे सकता है। नागरिक संस्थाएं संबंधित पक्षों को सूचना तथा दस्तावेज देने तथा शासन की एजेंसियों की आवश्यकताओं और मांगों का विश्लेषण कर सकती हैं। नागरिक संस्थाएं तिरस्कृत सामाजिक वर्ग जैसे गरीबों, महिलाओं और अक्षम-अपंग लोगों की आवाज बन सकती हैं जिनकी प्रायः उनके द्वारा चुने गए विधायिका एवं कार्यपालिका के सदस्यों द्वारा तथा अन्य माध्यमों से भी कम सुनवाई होती है। इस प्रकार नागरिक सक्रियता दावेदारों को शक्ति प्रदान कर सकती है और राजनीति को अधिक भागीदारी की ओर मोड़ सकती है।

3) **नीति निवेशः** सरकारी नीतियों का निर्माण न केवल घरेलू अपितु अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी नागरिक समाज के निवेश से अत्यधिक प्रभावित होता है। उदाहरण के लिए, नागरिकों के समूह कथित "वाशिंगटन सहमति" के प्रति बहस की चिंगारी भड़काने में आगे थे। उन्होंने निरंतर पर्यावरणीय असंतुलन के मुद्दों को भी उठाया, गरीबी का गुणात्मक आकलन किया और दक्षिण में ऋण में कटौती करने की योजनाओं के लिए दबाव बनाया।

4) **शासन में पारदर्शिताः** सतर्क नागरिक का लामबंद होना शासन में पारदर्शिता का कारण बन सकता है। नागरिक समाज का निरंतर दबाव नियमन के ढाँचों और क्रियाकलापों को उजागर करता है जहां जनता की निगरानी और नजर में उनका आकलन किया जा सकता है। प्रायः नागरिकों में यह जागरूकता नहीं होती कि सरकार द्वारा क्या निर्णय लिए जाते हैं, कौन लेता है और किन विकल्पों से, किस आधार पर, किन अपेक्षित परिणामों के लिए और लागू करने के लिए किन साधनों और संसाधनों के बल पर निर्णय लिए जाते हैं। नागिरक समाज अपने सुगठित ढाँचे के माध्यम से सरकार द्वारा "पारदर्शिता" की लगाई जाने वाली रट पर प्रश्न कर सकता है कि किसे पारदर्शी बनाया गया है, कब बनाया गया है, किसके निर्णय पर किस उद्देश्य से और किसके हित में क्या पारदर्शी बनाया गया है।

अभ्यास 21.1

नागरिक समाज क्या है? लोकतंत्र में इसके क्या कार्य हैं?

5) **जनता के प्रति जवाबदेहीः** नागरिक समाज कई संबंधित एजेंसियों को जनता के प्रति जवाबदेह बना सकता है। नागरिक समूह जनता और प्रेस से संबंधित नीतियों को लागू करने तथा उनके प्रभाव पर निगाह रख सकते हैं, यदि परिणाम विपरीत आ रहे हों। उदाहरण के लिए, स्वतंत्र नागरिक एजेंसियां विश्व बैंक और आई.एम.एफ. के मूल्यांकन की निष्पक्ष नीति रखती हैं। जिसके फलस्वरूप उन्होंने अल्प विकसित देशों के प्रति इन एजेंसियों की नीति की अधिकतर आलोचना की है।

   पश्चिमी देश जो व्यवहार में लोकतंत्र होने का दावा करते हैं प्रायः विश्व स्तर पर कभी-कभार उनसे भी अधिक तानाशाह हो जाते हैं जिनकी ये निंदा करते हैं तथा जिन पर पाबंदियां लगाते हैं।

6) **वैधताः** नागरिक समाज द्वारा पूर्व में की गई सभी गतिविधियों का कुल योग एक वैध लोकतांत्रिक शासन की ओर ले जाता है। जब लोग यह स्वीकार कर लेते हैं कि एक शक्ति को शासन करने का अधिकार है और उनका भी इसके निर्देशों की पालना करने का कर्त्तव्य है तो शासन वैध होता है। इस प्रकार की सहमति के परिणामस्वरूप वैध शासन अवैध शासन और तानाशाह सत्ता की तुलना में अधिक सरल, उत्पादक और अहिंसक ढंग से कार्य करता है।

यहाँ यह समझना महत्वपूर्ण है कि लोकतंत्र को राष्ट्रीय शासन की शर्तों पर नहीं समझना चाहिए। नागरिक समाज के पास वैश्विक शासन की नीति के अनुरूप लोकतंत्र का वृहद कार्यक्रम होना चाहिए। नागरिक समाज न केवल अपने घर पर ही लोकतंत्र को बढ़ावा दे सकता है अपितु इसका प्रभाव विश्व व्यवस्था में होते लोकतांत्रीकरण में भी देखा जा सकता है। नागरिक समाज नागरिकों में यह विश्वास पैदा करने के साधन उपलब्ध करवा सकता है कि वैश्विक शासन के प्रबंध को उनका मार्गदर्शन करना चाहिए और जहाँ आवश्यक हो वहां उनके व्यवहार पर बंधन भी लगाना चाहिए।

इसके अतिरिक्त मानव अधिकारों, महिला अधिकारों, विकलांगों के अधिकारों तथा पर्यावरण के प्रति अंतरराष्ट्रीय चिंता का गृह नीति निर्माण और इसे लागू करने पर बड़ा

असर पड़ता है। उदाहरण के लिए विकास कार्यों से संबंधित अनेक गैर-सरकारी संस्थाएं एवं विचार मंच, जो वैश्विक ऋणों में रियायतों एवं सामाजिक स्तर पर टिकने वाले ढांचागत समायोजन के लिए लाबिंग करते हैं, राष्ट्रीय एवं स्थानीय सरकारों में सरकारी खजाने की जाँच-पड़ताल तक पहुंचे हैं। इसके साथ ही महिला आंदोलनों ने प्रायः अंतरराष्ट्रीय कानूनों और संस्थाओं का अपने हित में प्रयोग कर लिंग के आधार पर राज्य को लोकतांत्रिक बनाने के लिए किया है। मानव अधिकारों के प्रति अंतरराष्ट्रीय चिंता से विकलांगों के अधिकारों को भी गति मिलती है।

21.8 नागरिक समाज के लोकतांत्रिक खतरे

नागरिक समाज का घरेलू और विश्व स्तर पर लोकतंत्र हेतु किया गया योगदान अति महत्वपूर्ण है। लेकिन यहां यह अवश्य जानना चाहिए कि नागरिक समाज वास्तव में कई प्रकार से अंतरराष्ट्रीय संबंधों के लोकतांत्रिक शासन से परे हटता है। ऐसी परिस्थितियों में नागरिक गतिविधियां अपनी लोकतांत्रिक शक्ति को अनुभव करने में असफल ही नहीं होती अपितु लोकप्रिय शासन को अवरुद्ध भी करती हैं। ऐसी सात नकारात्मक सम्भावनाओं को चिह्नित किया जा सकता है।

1) नागरिक समाज की गतिविधियां लोकतांत्रिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए नहीं भी हो सकतीं। यद्यपि नारिगक समाज शब्द ही नागरिकता और मूल्यों का परिचायक है परंतु व्यवहार में स्वैच्छिक संस्थाओं के कार्यक्रमों में लोकतंत्र को बढ़ावा देने के कार्यक्रम नहीं होते। इसके विपसीत ऐसी संस्थाओं के तत्व लोकतंत्र को नुकसान पहुचाने का कार्य कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, कुछ नागरिक संगठन (संस्थाएं) अपने तुच्छ उद्देश्यों की पूर्ति एवं सुविधाओं के लिए कार्य कर सकती हैं। जातिवाद, उग्र राष्ट्रवाद और धार्मिक कट्टरवाद फैलाने वाली विनाशकारी संस्थाएं दूसरों के लोकतांत्रिक अधिकारों के विरुद्ध काम कर सकती हैं। राजनीतिक रूप से प्रासंगिक इस्लामी वर्ग के उन भागों जैसे मुस्लिम भाई चारे ने समग्र रूप से लोकतंत्र के हित में कार्य नहीं किया है।

2) नागरिक समाज लोकतंत्र से दूर जा सकता है यदि इसके प्रयासों, आकार और क्रियान्वयन की योजनाएं ठीक से न बनाई गई हों। शासन के सांस्थानिक प्रबंध को समझे बिना ही यदि कार्यकर्ता काम करते हैं तो ये अपनी ही संस्था के मूल उद्देश्यों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। यहां तक कि शिक्षाविद् भी लोकतंत्र के सार्वजनिक उपयोग के अपने सैद्धांतिक प्रारूपों को उस विशेष क्षेत्र के विवेकसंगत अनुभवों एवं प्रमाणों से संबद्ध करने में असफल हो सकते हैं।

3) साधन विपन्न सरकारी एजेंसियां नागरिक समाज से प्राप्त जानकारियों को नहीं संभाल सकती। नियामक संस्थाओं में विशेषज्ञ स्टॉफ की कमी, पर्याप्त धनराशि तथा नागरिक समाज द्वारा प्रस्तुत लाभ के अवसरों का लाभ उठाने के लिए आवश्यक प्रवृत्ति अथवा अनुकूल तौर-तरीकों की कमी के कारण ऐसा हो सकता है। सरकारी अधिकारी नागरिक संस्थाओं के साथ नीति निर्माण के अंतिम चरण में विचार-विमर्श कर सकते हैं जब कि मुख्य फैसले लगभग हो चुके होते हैं। यह लोकतंत्र को बढ़ावा देने के स्थान पर समाज में बिगाड़ पैदा कर सकता है और उठा-पटक का कारण बन सकता है।

4) सरकार द्वारा दी गई धनराशि एवं लाभ नागरिक संस्थाओं के कार्यकर्ताओं को भ्रष्ट बना सकते हैं। अपने उद्देश्यों एवं लक्ष्यों पर ध्यान देने के स्थान पर वे अपने अल्पकालिक लाभों के लिए प्रयास कर सकते हैं।

5) अपर्याप्त प्रतिनिधित्व लोकतंत्र के मूल को नुकसान पहुंचा सकता है। यदि नागरिक समाज को अपनी सभी आवश्यकताओं को पूरा करना है तो नागरिक समाज के सभी स्तर के लोगों को अधिकारियों तक पहुंचने की छूट होनी चाहिए और भागीदारी के रूप में सबको लगभग समान अवसर उपलब्ध होने चाहिए अन्यथा नागरिक समाज में ढाँचागत असमानताएं तथा वर्ग, लिंग, राष्ट्रीयता, जाति, धर्म तथा शहरी बनाम ग्रामीण आधार पर मनमानी सुविधाओं में बढ़ोतरी तथा असमानताएं पैदा हो सकती हैं।

6) वैश्विक लोकतंत्र के प्रति नागरिक समाज की चिंता, स्थानीय सांस्कृतिक परम्पराओं के प्रति असंवेदनशील हो सकती है। इस संदर्भ में नागरिक समाज की स्थानीय लोगों की सभी समस्याओं के प्रति रुचि नहीं हो सकती। विशेष रूप से इस बात का खतरा है कि दक्षिण और पूर्व साम्यवादी देशों के नागरिक समाज पश्चिमी स्टाइल, पश्चिम द्वारा दी गई धनराशि से संचालित गैर-सरकारी संस्थाओं के प्रभाव में आ सकते हैं। ऐसे कार्यकर्ता वैश्विक शासन की प्रचलित स्थितियों की निन्दा कर सकते हैं और उनके स्थानीय समुदायों से अधिक भूमंडलीय प्रबंधकों के साथ मजबूत सांस्कृतिक संबंध हो सकते हैं। इस प्रकार गैर-सरकारी संस्थाएं एवं अन्य व्यावसायिक नागरिक समाज शायद चुपचाप अनायास ही उन आधारभूत वर्गों को हाशिये पर ला सकते हैं जो वैश्विक शासन को प्रभावित करने वाले विभिन्न जीव-समाजों की आवाज को मुखर कर सकते हैं।

7) नागरिक समाज में आंतरिक लोकतंत्र का अभाव हो सकता है। पर्याप्त लोकतंत्र के लिए काम करने वाले विशिष्ट समूहों सहित नागरिक समाज समूह अपनी कार्यविधि में लोकतांत्रिक व्यवहार से परे हो सकते हैं। नागरिक समाज के क्षेत्र में आंतरिक लोकतंत्र का अभाव न केवल अपने लिए ही दोषयुक्त है अपितु पूरे समाज में लोकतंत्र लाने के बड़े उद्देश्य के भी विरुद्ध है। प्रायः यह देखा जाता है कि नागरिक संस्थाएं अपने सदस्यों को चन्दा देने से अधिक प्रतिभागिता के अवसर कम ही देती हैं। नागरिक समाज की संस्थाएं कुछ क्षेत्रों और लोगों की, उनसे विचार विमर्श किए बिना वकालत कर सकती हैं। नागरिक समाजों का नेतृत्व कल्याण के नाम पर बहस को दबा सकता है। नागरिक समूहों में पारदर्शिता का अभाव हो सकता है क्योंकि कभी-कभी वे आर्थिक ब्यौरा, अथवा अपनी संस्था के उद्देश्यों की घोषणा तक को प्रकाशित नहीं करते, पूरे प्रतिवेदन का तो सवाल ही नहीं पैदा होता।

इन ज्वलंत समस्याओं के दृष्टिगत हमें घरेलू और अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में लोकतंत्र को बढ़ावा देने वाली एजेंसी के रूप में नागरिक समाज के प्रति अपने उत्साह को पर्याप्त सावधानी और ध्यान से संतुलित करना चाहिए। किसी को नागिरक समाज की मोहक कपोल कथाओं से नहीं बहकाना चाहिए। बहुत कुछ ठीक हो सकता है परंतु बहुत कुछ गलत भी हो सकता है। नागरिक समाज अच्छे लक्ष्य के लिए साधन हो सकता है परंतु अपने आप में अंतिम लक्ष्य नहीं है। ऐसे उदाहरण और परिस्थितियाँ हैं जब नागरिक समाज की भागीदारी लोकतंत्र से दूर ले जा सकती है अथवा लोकतंत्र के मूल पर आघात कर सकती है। समाज की यह पहली मांग होनी चाहिए कि नागरिक समाज को न केवल अपने को दृढ़ करना चाहिए अपितु अपनी लोकतांत्रिक वैधता को दर्शाना चाहिए।

अभ्यास 21.2

नागरिक समाज और लोकतंत्र में क्या संबंध है?

इसके साथ ही यह स्पष्ट निष्कर्ष निकाल लेना चाहिए कि जो लोकतंत्र का प्रसार करते हैं या विदेशों में लोकतंत्र के लिए धनराशि प्रदान करते हैं — वे स्वयं भी अपने व्यवहार

में लोकतांत्रिक हैं। अमरीका ने 1991 से ही मध्य-पूर्व में लोकतंत्र की समर्थक कई संस्थाओं की सहायता की है। 1991 से 2000 तक मध्य-पूर्व में दी गई सहायता लगभग 150 मिलियन डालर थी। इन प्रकल्पों को नागरिक समाज सशक्तीकरण के रूप में वर्गीकृत किया गया था। 1994 में पैलेसटीनियन अथार्टी (फिलीस्तीनी अधिकरण) बनने के बाद इजरायल के कब्जे के दौरान अमरीका ने वेस्ट बैंक और गाजा में कुछ फिलिस्तीनी संस्थाओं को आर्थिक सहायता प्रदान की। संयुक्त राज्य अमरीका ने इस सहायता को बढ़ाया और इसे नागरिक समाज सशक्तीकरण के रूप में वर्गीकृत किया। वर्ष 2000 में अमरीका ने 32 मिलियन डालर का एक प्रोजेक्ट फिलिस्तीनी गैर-सरकारी संस्थाओं को समर्थन एवं सहयोग देने के लिए प्रारंभ किया। लेबनान में अमरीकी सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत 1990 में समुदाय आधारित सेवा करने वाली संस्थाओं की सहायता के लिए कई मिलियन डालर खर्च किए ।

अमरीकी प्रयासों का सर्वोपरि तत्व था "नागरिक समाज को सहायता प्रदान करना।" केवल लोकतंत्र को बढ़ावा देना ही इन प्रकल्पों का तर्क नहीं था। मिस्र में अमरीका का विश्वास था कि प्राइवेट समूहों को विकास के कार्यों में विस्तृत भूमिका प्रदान करने से इसकी (अमरीका की) आर्थिक उदारीकरण की नीति के उद्देश्य को आगे बढ़ावा मिलेगा। वेस्ट बैंक और गाजा में अमरीका को फिलिस्तीनी संस्थाओं (गैर-सरकारी संगठनों) को स्वशासन के अंतर्गत अपनी जीवन स्थितियों को सुधारने के लिए सहायता प्रदान करने से ओसलो शांति प्रक्रिया के प्रति जन समर्थन जुटाने की आशा थी। (इसके साथ ही एन.जी.ओ. सहायता को दिशा देने में प्रमुख हथियार थीं क्योंकि कांग्रेस ने अमरीका पर फिलिस्तीनी प्राधिकरण को सीधे सहायता देने पर पाबंदी लगा रखी थी)।

लेबनान में अमरीका स्थानीय समुदायों को गृह युद्ध की त्रासदी के बाद पुनर्निर्माण के लिए सहायता करना चाहता था। क्योंकि सरकारी एजेंसियां बहुत कमजोर थीं, इसलिए सामुदायिक संस्थाएं और गैर-सरकारी संस्थाएं सहायता में बेहतर भागीदार थीं। क्लिंटन के प्रशासन के दौरान इस्लाम एक कारक बन गया था यद्यपि खुले रूप से इसे स्वीकारा नहीं गया था। कुछ अमरीकी अधिकारी गैर-सरकारी सैनिक संस्थाओं को इस्लामी सहायता तथा दूसरे समूहों की मजबूत काट मानते थे। ऐसी संस्थाएं इस्लाम विरोधी आंदोलनों की आधारभूत सहायता की स्रोत थीं और इस कारण वंश अमरीकी अधिकारी संसाधनों को इन संस्थाओं की ओर मोड़ना चाहते थे। यद्यपि 1991 और 2003 में जब अमरीका ने ईराक और अफगानिस्तान जैसे छोटे देशों पर आक्रमण किया तब अलोकतांत्रिक साधनों से अमरीका की वैश्विक लोकतंत्र के प्रति वचनबद्धता को आसानी से समझा जा सकता है। लोकतंत्र के प्रति अमरीका का प्यार कोई नया नहीं है। लोकतंत्र के नाम पर अमरीकी राष्ट्रपतियों द्वारा (विशेष रूप से उल्लेखनीय राष्ट्रपति विल्सन, 1913 - 21) पूरे मैक्सिको, केंद्रीय अमरीका और कैरेबियन पर लगभग दो दर्जन आक्रमण, जीवित रहने वाला, एक भी लोकतंत्र पैदा नहीं कर सके। पिछले कुछ उदाहरण और अधिक आँख खोलने वाले हैं जिनमें अमरीका ने लोकतंत्र स्थापना के निहित उद्देश्य से जोर जबर्दस्ती से बलपूर्वक तानाशाह शासकों को खदेड़ा जैसे, 1992 में पानामा, 1994 में हैथी और 2002 में अफगानिस्तान। इन अनुभवों में से किसी एक को भी सफल लोकतंत्रीकरण का उदाहरण नहीं माना जा सकता।

21.9 सारांश

घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लोकतंत्र के कार्यात्मक एवं प्रोत्साहनात्मक पक्ष के संदर्भ में नागरिक समाज का गहराई से अध्ययन करने पर हम ऐसी उलझी हुई स्थिति में पहुंचते हैं, जो लोकतंत्र का सर्वश्रेष्ठ और सार्वभौमिक शासन व्यवस्था के रूप में प्रचार करती है। वे स्वयं अपने हितों के लिए और कभी कभी तो तुच्छ हितों के लिए इससे दूर

हट जाते हैं। फिर भी इस पर कोई दो मत नहीं हो सकते कि नागरिक समाज ने लोकतंत्र के कार्यान्वयन के लिए सुविधाजनक मार्ग प्रदान करने में सहायता की है। लेकिन यह धारणा भी उतनी ही खतरनाक एवं खुद पर थोपने जैसी है कि अल्प विकसित देशों को नागरिक समाज और लोकतंत्र का पाश्चात्य प्रारूप अपनाना चाहिए।

इस विषय पर पर्याप्त शैक्षणिक चर्चाएं हुई हैं कि कुछ मानव जीवन रचनाशास्त्री यह प्रश्न करते हैं कि क्या नागरिक समाज का सिद्धांत पश्चिम से बाहर भी लागू होता है। उदाहरण के लिए, चीन और ताइवान के तुलनात्मक अध्ययन में राबर्ट पी. वैलर लिखते हैं "मैंने इसके मूल मुद्दों को लिखते समय "नागरिक समाज" शब्द का प्रयोग जानबूझकर नहीं किया। नागरिक समाज शब्द के साथ अनेक समस्यात्मक सैद्धांतिक पूर्वानुमान और ऐतिहासिक अर्थ जुड़े हुए हैं जिनकी एक विशेष यूरोपीय दार्शनिक परम्परा में गहरी जड़े हैं। राजनीतिक विचारक सुदिप्ता कविराज और सुनील खिलानी नागरिक समाज के सिद्धांत के संबंध में अधिक वर्णनात्मक कारण देते हैं "यूरोपीय उपनिवेशवाद के आगमन से राज्य, सामाजिक जीवन का एक स्वीकार्य और आवश्यक अंग बन गया और आधुनिक समाज की संस्थात्मक व्यवस्था राज्य और नागरिक समाज में भेद के लिए संवाद और भाषा के अवसर पैदा करती है। यद्यपि उन्होंने अधिकांशतः औपनिवेशिक संदर्भ में राज्य और नागरिक समाज के आगमन के प्रति विचार विमर्श को प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है।

इस विषय का अधिक सैद्धांतिक संदर्भ में मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित बिंदु इस विषय की वर्तमान जटिलताओं को समझने के लिए उपयोगी हो सकते हैं। पहले तो प्रवक्ता प्रायः नागरिक समाज को पूर्णतया सकारात्मक दर्शाते हैं — यहाँ तक कि इसमें कोई कमी नहीं देखते। उदाहरण के लिए एक लेख "सिविल सोसायटी और बिल्डिंग डेमोक्रेसीः लेसन्स फ्रॉम इंटरनेशनल डोनर एक्सपीरेंस" (नागरिक समाज और लोकतंत्र निर्माणः अंतरराष्ट्रीय सहयोग अनुभव से सीखे पाठ) में हैरी ब्लेयर कहते हैं कि नागरिक समाज की संस्थाएं नीति निर्माण की प्रक्रिया में नागरिकों की प्रतिभागिता को बढ़ाती हैं, नागरिकों के प्रति राज्य की जवाबदेही में वृद्धि करती हैं तथा लोकतांत्रिक राजनीति में नागरिक शिक्षा प्रदान करती हैं। यह एक आदर्श का वर्णन है, एक ऐसा आदर्श जिसने 1989 से अंतरराष्ट्रीय अनुदानों के माध्यम से नागरिक समाज की संस्थाओं को सैकड़ों मिलियन डालर की सहायता के लिए प्रेरित किया और इसका मिला-जुला परिणाम रहा।

दूसरे जो लोग नागरिक समाज को आदर्श मानते हैं वे प्रायः नागरिकों के कार्यों के बारे में बात करते हैं परंतु नागरिक, संघर्ष की बात नहीं करते। फिर भी संसाधनों, कानूनों, नीतियों पर विवाद का प्रभाव केंद्र में रहता है और हितों की अनेकता के कारण नागरिकों के दिलों पर होता है। इस कारण कट्टर वादी समाज जो सत्य के एक ही स्रोत में विश्वास रखते हैं, जैसे — स्टालिन के नेतृत्व में सोवियत रूस अथवा बीसवीं सदी के अंत में दूसरे साम्यवादी देश या आयतुल्ला खुमैनी के नेतृत्व तले ईरान। ये दृष्टिकोण में अनेकता का स्वागत करने वाले समाजों की तुलना में नागरिक समाज को कम पसंद करते हैं।

तीसरे टौक्युवेली के बाद से पाश्चात्य विचारकों ने व्यक्तिवाद को नागरिक समाज के दिल में बैठा दिया। उदाहरण के लिए, एर्नेस्ट जेलनर नागरिक समाज के निर्माणकर्ता को माडुलर मैन कहता है, जो है तो स्वायत्त, परंतु जुड़ने के लिए तैयार भी और सक्षम भी है। दुनिया के अधिकांश भागों में लोग स्वयं को माडुलर नहीं समझते। वे किसी विशेष समुदाय (परिवार, धर्म, वंश, जाति, कुल अथवा किसी अन्य के आधार पर) का सदस्य होने के रूप में अपनी पहचान को पक्का मानते हैं न कि आसानी से बदलने वाला। उदाहरण के लिए, साकत केंद्र - (Sakete centre) में मुसलमान, ईसाई और स्थानीय देवताओं को मानने वाले इकट्ठे रहते हैं तथा मुसलमान और ईसाई कड़ी मुसीबत में स्थानीय देवताओं के लिए त्याग करते हैं। फिर भी दूसरे के रीति-रिवाजों और व्यवहार के प्रति इस खुलेपन का यह अर्थ नहीं है कि वे माडुलर हैं और एक पंथ को दूसरे के साथ

आसानी से बदल सकते हैं। परिवार और वंश की भांति धर्म भी व्यक्ति को सामाजिक संबंधों के जाल में फंसा देता है जिसे कोई बड़ी कीमत देकर ही काटा जा सकता है। नागरिक समाज का मूल विचार इस धारणा पर टिका है कि व्यक्ति सामाजिक होने के कारण चुनौतियों से घिरा है। यदि लोगों को माडुलर माना जाता है तो हम ऐसे नागरिक समाज की कोई परिभाषा कैसे बना सकते हैं जो राष्ट्र से परे भी काम करता हो।

चौथे नागरिक समाज की अवधारणा के साथ विस्तृत मानदंड रखे गए हैं। कुछ का तर्क है कि नागरिक समाज में परिवार को छोड़कर गैर राज्यीय संस्था के सभी प्रकार या स्वरूप सम्मिलित हैं परंतु यह मानने योग्य बात नहीं है क्योंकि नागरिक समाज में ही कई सामाजिक संस्थाएं सम्मिलित हैं, जो अनिवार्य रूप से प्राइवेट हैं और इसी कारण नागरिक समाज़ और समाज में अंतर कर पाना संभव नहीं होता। सिद्धांत को अधिक उपयोगी बनाने के लिए नागरिक समाज के नागरिक पक्ष में उन सभी ढाँचों, आंदोलनों और संस्थाओं की श्रेणी को शामिल करना चाहिए जिनका आयाम जनता का पक्ष हो।

पाँचवें, यहाँ इस बात पर बल है कि नागरिक समाज की प्रकृति दोहरी है। उद्‌गम में पूर्णतया निजी परंतु ध्यान से देखने पर सार्वजनिक। नागरिक समाज समूह प्रायः अहिंसक जन साधनों का प्रयोग कर निजी हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं जैसे संस्थाएं, शिक्षा तथा नीति और राजनीति को प्रभावित करने के लिए प्रदर्शन भले ही वे पड़ोस में हो अथवा शहर, क्षेत्र, राज्य अथवा राष्ट्रीय स्तर पर हो। ये हित व्यक्तिगत हित भी हो सकते हैं या धर्म, वंश या अन्य सामाजिक समूहों से संबद्ध हित भी हो सकते हैं। एक प्रकार से इनसे सरकार पर दवाब बनेगा।

नागरिक समाज पर अपनी चर्चा को सकारात्मक शैक्षणिक विचार के साथ पूरा करने के लिए जो विचार, व्यवहार में अपनाया गया है वह है कि लोकतंत्र, स्वस्थ और सक्रिय नागरिक समाज की आवश्यकता है। अंतरराष्ट्रीय समुदाय, विभिन्न नागरिक समूहों को संसाधन एवं प्रशिक्षण देकर देशों को लोकतांत्रिक बनाने में स्थानीय नागरिक समूहों के निर्माण में सहायता कर सकते हैं।

ठीक उसी समय लोकतंत्र के नाम पर अपने विचारों और संस्कृति को नागरिक समाज पर थोपने में पूरी सावधानी बरतनी चाहिए। यद्यपि स्थानीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लोकतंत्र, शासन की स्वस्थ व्यवस्थाओं में से एक है, परंतु सामाजिक विज्ञान में कोई शब्द अंतिम नहीं होता। पूर्व में कई प्रकार की प्राचीन सांस्कृतिक व्यवस्थाएं और रीति-रिवाज रहे हैं जो आज के पाश्चात्य जीवन से कहीं बेहतर थे। उन्हें इसलिए नहीं छोड़ देना चाहिए कि पश्चिम के संबंध में हमारी रुचि और अपनी कल्पनाएं हैं । यह अधिक महत्वपूर्ण है कि अच्छी जीवन पद्धति को बढ़ावा देने के लिए चर्चा और उत्साह बने रहना चाहिए जिससे सर्वसत्तात्मक और तानाशाह राज्यों में अत्यंत गरीबी और कष्ट में जीने वाले लोगों का भला हो सके।

21.10 कुछ उपयोगी पुस्तकें

हैरी ब्लेयर, 'सिविल सोसायटी एंड बुल्डिंग डेमोक्रेसीः लेसन्स फ्रॉम इंटरनेशनल डोनर एक्सपीरियेंस' पीपी 65-80 इन बर्नार्ड, हेलमिल्क एंड लेहनिंग (एडी.) सिविल सोसायटी एंड इंटरनेशनल डेवलपमेंटस। नॉर्थ-साउथ सेंटर ऑफ द कौंसिल ऑफ यूरोप, डेवलपमेंट सेंटर ऑप द आर्गेनाइजेशन फार इकोनॉमिक को-ऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, 1998.

सुदिप्ता कविराज एंड सुनील खिलानी, 'इंट्रोडक्शनः आइडियाज ऑफ सिविल सोसायटी इन सिविल सोसायटीः हिस्ट्री एंड पॉसिबिलिटीज (कैम्ब्रिज, यूकेः कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस, 2001).

डॉ. अर्चिबुगी एंड डी हेल्ड (एडी.) कॉस्मोपोलिटन डेमोक्रेसीः एन एजेंडा फार ए न्यू वर्ल्ड ऑर्डर (कैम्ब्रिजः पॉलिटी, 1995).

डेविड हेल्ड, माडल्स ऑफ डेमोक्रेसी (स्टेनफॉर्ड, क्लिफः स्टेनफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 1987).

एर्नेस्ट गेलनर, 'सिविल सोसायटी इन हिस्टोरिकल कॉटेक्स्ट', इंटरनेशनल सोशल साइंस जर्नल (अगस्त, 1991) - 495-510.

गॉर्डन व्हाइट, 'सिविल सोसायटी, डेमोक्रेटाइजेशन एंड डेवलपमेंट (1) - क्लियरिंग द एनालिटिकल ग्राउंड', डेमोक्रेटाइजेशन, वाल्यूम 1, नं. 3 (ऑटम्न 1994).

नीरा चंढोक, 'द सिविल एंड द पॉलिटिकल इन सिविल सोसायटी', डेमोक्रेटाइजेशन, वाल्यूम 8, नं. 2 (समर 2001) - 1-24.

खंड 6

संजातीयता और पहचान के समकालिक मुद्दे

खंड 6 प्रस्तावना

इस खंड में संजातीयता और पहचान के कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई है। सबसे पहले शिक्षार्थी को संजातीयता की संकल्पना को किस प्रकार समझना है, इसके बारे में बताया गया है। इसके बाद पुस्तक में पहचान-निर्माण का विश्लेषण और वर्णन किया गया है और अंत में, इस पुस्तक में संजातीयता की संकल्पना और समकालिक संदर्भों तथा पहचान-निर्माण के परिप्रेक्ष्य में सीमाओं और सीमाओं के अनुरक्षण के मुद्दों की जाँच की गई है।